

सेवा सेतु अभियान के तहत सरकार आपके द्वार शिविर में 113 आवेदन, फ़िर भी कम रही आमजन की भागीदारी

16 प्रकरणों का मौके पर निराकरण, कई विभागीय स्टॉल रहे सूने; प्रचार-प्रसार पर उठे सवाल

संदीप मिश्रा पाटन
पाटन(जनात के गोठ)।
जनपद पंचायत जनता द्वारा सेवा सेतु अभियान के तहत सतनाम भवन में 'सरकार आपके द्वार' शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित कुल 113 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 16 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों से संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

हालांकि, शिविर के दौरान आम जनता की अपेक्षकृत कम भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कुर्सियाँ खाली नजर आईं। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए कई स्टॉल पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्टॉल पर मौजूद रहे।

व्यापक प्रचार-प्रसार का अभाव बना चर्चा का विषय
आमजन की कम उपस्थिति के बीच स्थानीय स्तर पर शिविर के पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं होने की चर्चा होती रही। लोगों का कहना था कि यदि आयोजन से पहले गांवों और नगर क्षेत्र में व्यापक जानकारी पहुंचाई जाती तो अधिक संख्या में



लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर शिविर तक पहुंच सकते थे। सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए स्टॉल पर

अपेक्षित संख्या में लोगों की मौजूदगी नहीं होने से आयोजन की उपयोगिता को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं।

सांसद ने किया विभागीय
स्टॉल का निरीक्षण



शिविर में पहुंचे सांसद विजय बघेल ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में देश के विकास और विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सुविधाएँ पहुंचाने का कार्य कर रही है।

को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिविर में नगर-पंचायत अध्यक्ष योगेश निक्की बाला, जनपद अध्यक्ष कीर्ति नायक, जिला पंचायत सदस्य नीलम राजेश चंद्रकार, अमलेश्वर पालिका अध्यक्ष दयानंद सोनकर, सांघत प्रतिनिधि राजा पाठक, मंडल अध्यक्ष कमलेश साहू, रानी केशव बंछेर, ज्योति प्रकाश साहू, लोकमणि चंद्रकार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हर्षा चंद्रकार, जनपद उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, राजेश चंद्रकार, बाबा वर्मा, डॉ. सुरेश साहू, चंद्रिका साहू, केवल देवांगन, रानी बंछेर, पारखत साहू, राजू साहू, निशा सोनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक संपन्न

लंबित कार्य सीआईआरपी के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

बलरामपुर (जनता के गोट)
: कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला जल एवं सस्वच्छ मिशन की बैठक गुवागार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, योजनाओं की अद्यतन प्रगति तथा पूर्ण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं अधिकारियों को लक्षित कार्य शीघ्र पूर्ण करने और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्यक्ष निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एजेंडा के अनुसार बिंदुवार चर्चा की गई। विभिन्न निविदाओं की दर स्वीकृति, अनुबंधों के अंतर्गत समयावृद्धि तथा निरस्त अनुबंधों जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए विचार-विमर्श किया गया। अक्टूबर 2022 तक पूर्ण की जाने वाली 776 योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के साथ डीएमफ मद से बोर खनन, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जल जल सेवा संकल्प के क्रियान्वयन तथा जल अर्पण दिवस के आयोजन पर भी



पचाई की गई। जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला एवं एम्प्टीके क्विट से किए जा रहे जल परीक्षण की प्रगति की समीक्षा हुई, वहीं क्रेडा विभाग द्वारा सोनर पंप स्थापना में आ रही समस्याओं की भी चर्चा कर समाधान के उपायों पर विचार किया गया। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सीआईआरपी में अनुसार निर्धारित समय-सीमा में नसीब कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गति दी जाए उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता माफकों का विशेष ध्यान रखने तथा नियमित निगरानी पर जोर दिया, ताकि जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को

कार्यों को तेजी से तैयार और निष्पक्ष करने, निर्माण में सेतु लाने और लक्ष्यों के अनुसंधान प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने देने के निर्देश दिए। बैठक में ठेकेदारों के देखकों का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में भी दिशानिर्देश दिए गए, जिससे पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों में निरंतरता बनी रहे और योजना का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। बैठक में जिला प्रचालय सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपाठन अभियंता पंकज जैन, एवं अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सेवा संकल्प अभियान: जिला चिकित्सालय में 16 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन

आँखों की रोशनी वापस लौटने से मरीजों में खुशी, निःशुल्क जाँच, उपचार एवं दवाइयों का मिला लाभ

जनता के गोठ बलरामपुर : सेक्टर संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय बलरामपुर में विशेष चिकित्सकों की टीम द्वारा 16 मरीजों को मोतिब्याबंद का सफ्त ऑपरेशन किया गया। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के अंतिम स्थाई तक सुभानु प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन के उपरांत सभी मरीजों को आवश्यक दवायाँ तथा देखभाल संबंधित चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। जिससे दृष्टि लौटने पर मरीजों ने शासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा ए



स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह तथा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. विवेक सिंह ने बताया कि मोतियाबिंद दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है, जिसे समय पर जाँच व

ऑपरेशन के माध्यम से पूरी तरह से
किया जा सकता है। उन्होंने जिलेव
विशेषकर 60 वर्ष से अधिक अ
नागरिकों से अपील की है कि ऑ
धुंधलापन या दृष्टि संबंधी समस्या ह

निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या जिले के चिकित्सालय में अपनी जाँच अवश्य कराएँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में नेत्र परीक्षण एवं उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

चंदौरा: घाटपेण्डारी घाट में पलटे ट्रक से 1.19 करोड़ का गांजा बरामद

जाहिद अंसारी (जनता के
गोठ)।



हुई थीं। तलाशी के दौरान सड़क किनारे गड्ढे में तिरपाल से ढंकाकर रखी 9 बोरियों से 238 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रक, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है, तथा प्लास्टिक दाने से भरई 19 बड़ी बोरियां भी जब्त की हैं।

उड़ीसा से लखनऊ ले जा रहे थे गांधी- विवेकानंद के दौरान पुलिस ने फ़ार आरोगी सुनील कुमार पति लक्ष्मण सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी इंद्रानगर खैरी रोड, थाना देहली गेट, जिला अलीढ़ा (उत्तरप्रदेश) को दबिश देकर गिरफ्तार किया। पृष्ठछाह में आरोपी ने पुलिस को बताया कि ट्रक अलीढ़ा निवासी उसके साथी के नाम पर पंजीकृत है और वह पाठनरशिष में ट्रक के दोबख करता था। ट्रक में हाथरस निवासी

चालक के माध्यम से उड़ीसा से प्लास्टिक दाने के साथ गांजा लोड कर लखनऊ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 29 सितंबर को घाटपेण्डरी घाट में ट्रक पलट गया, जिसके बाद गांजा को सड़क किनारे गड्ढे में छिपाकर तिरपाल से ढंक दिया गया था। पुलिस ने मामले में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा, ट्रक और अन्य सामग्री जब्त की है। मामले में फ़ार अन्वारेओपियो की पतासाजी की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदौर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, प्रधान आरक्षक शैलेश सिंह, भगवत अयाल पैकरा तथा आरक्षक दयाल तिवारी, अवधेश कुशवाहा, सूरज पाटिल, विजय गुप्ता, कमरेश यादव, अमृतलाल जगत, अशोक कुमार शर्मा और मनोज राजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।

नीलकण्ठ धिरहे (जनता के गोट)। सक्ती। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक तरुण प्रकाश के चांपा से रायगढ़ स्टेशन तक प्रस्तावित निरीक्षण दौरे के दौरान बाराङ्गर स्टेशन में जनप्रतिनिधियों एवं अन्य क्षेत्र के नागरिकों ने उस मुलाकात कर स्थानीय सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न मांग रखीं। इस दौरान निर्वाचन प्रशासक आनंद कुमार शर्मा ने महाप्रबन्धक से मुलाकात कर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही रेल सर्वध्वंस समस्याओं एवं यात्री सुविधाओं को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बाराबदर रेलवे स्टेशन पर प्रमुख दोनों के उद्घाव सहित क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रारम्भ प्रमुखता से रखी गई। आयुक्त शर्मा ने बाराबदर स्टेशन पर हीराकुट एक्सप्रेस से एवं दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के उद्घाव की मांग की। उन्होंने बताया कि इन दोनों के उद्घाव से क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी तथा सक्ती जिले के सीमा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिल सकेगी।

इसके अलावा सकरेली एवं भगोडीह में अंडरग्रिड निर्माण की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई। स्थानीय स्तर पर रेलवे क्रॉसिंग एवं आवागमन से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए इन स्थानों पर अंडरग्रिड की आवश्यकता बताई गई। अंडरग्रिड बनने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और अन्य राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ रेलवे लाइन पर करने से जुड़ी परेशानियां कम होने

आवागमन को देखते हुए आरओबी निर्माण को महत्वपूर्ण बताते हुए रेलवे महाप्रबंधक का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कराया गया। इसके साथ ही जेठ रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन के उतराव की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। मेमू ट्रेन के उतराव से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को सुविधा मिलने की बात कही गई।

की उम्मीद है। मुलाकात के दौरान आयुध ज्ञापन में बाराद्वार में रेलवे शर्मा ने क्षेत्र की रेलवे से संबंधित आवश्यकताओं और स्थानीय लोगों की मांग भी रखी गई। क्षेत्र में बढ़ते की अपेक्षाओं से महाप्रबंधक को

[illegible]

रेल महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने जिला पंचायत सभापति आयुध शर्मा द्वारा रखे गए सभी विषयों पर चर्चा की और संबंधित मांगों के लेकर सकारात्मक रूप से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित स्थानों का जल्द अवलोकन करवाने की बात कही, ताकि मौके की स्थिति का

[illegible]

यात्रा को लेकर आवश्यक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

बाराद्धर स्टेशन में महाप्रबंधक के निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मौजूदगी में क्षेत्र की रेल सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने आने से स्थानीय लोगों को इन मांगों पर आगे कार्रवाई की उम्मीद जगी है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि प्रमुख ट्रेनों का ठहराव, अंडरब्रिज एमू आओबी निर्माण तथा जेठ में मेमू ठहराव जैसी मांगें पूरी होती हैं, तो इससे सक्ती क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिल सकती है।

संपादकीय

हरियाणा में आम लोगों को खुद जांच कराने की सुविधा मुहैया कराने का सरकार का फैसला महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर बाजार से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी जांच कराने की जिम्मेदारी विभागीय कर्मियों की होती है। शुद्ध और सुरक्षित भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है। मगर कुछ लोगों ने खाद्य पदार्थों के बाजार में मिलावट को मुनोफे का औजार बना लिया है। यह केवल कानून के उल्लंघन का प्रश्न नहीं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य और विश्वास

के साथ खिलवाड़ का भी मसला है। रोजमर्रा के जरूरी खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाइयां, दालें और यहां तक कि फलों एवं सब्जियों में भी मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं।इस स्थिति में हरियाणा में आम लोगों को खुद जांच कराने की सुविधा मुहैया कराने का सरकार का फैसला महत्वपूर्ण है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर तैनात संचालित प्रयोगशालाओं में कोई भी व्यक्ति खाद्य वस्तुओं की जांच करा सकता है,

जिनका नतीजा दस से बारह मिनट में मिल जाएगा।अन्य राज्यों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष हो।भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पहले से लागू है। असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामलों में कठोर दंड और मृत्यु जैसे गंभीर परिणामों पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान भी मौजूद है। फिर भी यदि मिलावटखोरों में कानून का भय नहीं है, तो

समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके प्रभावी अमल की है।गंभीर मिलावट के मामलों के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था और समयबद्ध सुनवाई आवश्यक है। नमूना जांच से लेकर अभियोजन तक प्रत्येक चरण की समयसीमा तय हो। दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस रद्द करने, कारोबार बंद कराने और आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई प्रभावी हो। बार-बार अपराध करने वालों के लिए दंड कई गुना कठोर होना चाहिए। यदि मिलावटी खाद्य पदार्थ से किसी व्यक्ति को

गंभीर बीमारी, स्थायी क्षति अथवा मृत्यु होती है, तो ऐसे मामलों में कम-से-कम आजीवन कारावास जैसी कठोरतम सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों में केवल कंपनी पर जुर्माना लगाकर जिम्मेदारी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिन निदेशकों, संचालकों अथवा जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी, सहमति या लापरवाही से मिलावटी खाद्य बाजार में पहुंचा, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो। अपराध से अर्जित लाभ जब्त करने और पीड़ित

परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था भी आवश्यक है।खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। नमूना कब लिया गया, किस अधिकारी ने लिया, किस प्रयोगशाला में भेजा गया, रिपोर्ट कब आई और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई—इन सभी चरणों का डिजिटल रिकॉर्ड सार्वजनिक निगरानी के दायरे में होना चाहिए। अधिकारियों की मिलीभगत या जानबूझकर की गई लापरवाही को भी गंभीर अपराध माना जाए।

यहीं सरकार के कार्य की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी सामने आती है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई। यानी एक दशक में करीब 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। मानव इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की यह संख्या दुनिया में दर्ज की गई सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस बदलाव में वित्तीय समावेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से करीब 58 करोड़ भारतीय औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, जिनमें लगभग आधी महिलाएं हैं। इनमें से बहुत से लोगों के लिए बैंक खाता और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का यह पहला अनुभव था। इसी मजबूत आधार पर यूपीआई का विस्तार हुआ।

(आदित्य त्रिवेदी)

गुजरात की बागडोर एक संकटग्रस्त राज्य के रूप में संभालने के पच्चीस वर्ष बाद, नरेंद्र मोदी का शासन मॉडल एक आत्मविश्वासी और परिणाम देने वाले भारत की आधारशिला बन चुका है।गुजरात की बागडोर एक संकटग्रस्त राज्य के रूप में संभालने के पच्चीस वर्ष बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की शासन-यात्रा ने एक ऐसे भारत को परिभाषित किया है, जो अधिक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी है तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निर्धारित राष्ट्रीय प्रार्थमिकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। जब नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा था। भुया के भूकंप ने शहरों और कस्बों को तबाह कर दिया था, आर्थिक विकास नकारात्मक हो गया था और नए मुख्यमंत्री के सामने गुजरात को उबारने तथा उसका पुनर्निर्माण करने की एक बड़ी चुनौती थी।पच्चीस वर्ष बाद, उस राहत और पुनर्निर्माण के अभियान ने हमारे समय की सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली शासन-यात्राओं में से एक का रूप ले लिया है।जिन लोगों को नरेंद्र मोदी जी के साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला है, वे जानते हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान एक सिद्धांत निरंतर बना रहा है; वह है लोककल्याण सुनिश्चित करने के साधन के रूप में सुशासन में उनका विश्वास। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों के आने से बहुत पहले ही प्राचीन भारतीय चिंतन में इस विचार को अभिव्यक्त किया गया था। भगवद्गीता कर्म में कुशलता को योग के एक रूप के रूप में प्रस्तुत करती है। मोदी जी के लिए शासन का संबंध कर्मयोग की अवधारणा से गहराई से जुड़ा रहा है, अर्थात् दूसरों की सेवा के लिए किया गया कर्म, जिसमें परिणाम और पंक में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हो। गुजरात के वर्षों के कुछ आंकड़े इस दृष्टिकोण की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2001 से 2012 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.6 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र में भी 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गुजरात को व्यापक रूप से एक औद्योगिक राज्य के रूप में देखा जाता था। इसने विकास के स्रोतों को लेकर बनी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। 2003 में शुरू हुए वाइब्रेट गुजरात समिट ने राज्य को निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद की। देश की लगभग पांच प्रतिशत आबादी वाले गुजरात ने भारत के कुल विदेशी निवेश का पांच से सात प्रतिशत आकर्षित किया। गुजरात में उस विकास की नींव रखी जा रही थी, जो आगे चलकर राष्ट्रीय विकास की एक व्यापक गाथा का आधार बनी। 2014 में मोदी जी के राष्ट्रीय मंच पर आने के साथ गुजरात का यह अनुभव 1.4 अरब लोगों वाले देश के शासन तक पहुंचा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अब भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है और अनुमान है



कि 2026 की तीसरी तिमाही में भारत की नाममात्र जीडीपी चार ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। एक दशक से कुछ अधिक समय में भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यह बदलाव देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को वैश्विक स्तर पर कहीं अधिक व्यापक मंच पर ले गया है। लेकिन आर्थिक विकास को केवल बैलेंस शीट के आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। इसका वास्तविक महत्व इस बात में है कि इसका लाभ देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक कितना पहुंचता है और उनके दैनिक जीवन में कितना सुधार लाता है। यहीं संस्कार के कार्य की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी सामने आती है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई। यानी एक दशक में करीब 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। मानव इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की यह संख्या दुनिया में दर्ज की गई सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस बदलाव में वित्तीय समावेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोदी जी के प्रधानमंत्री पद संभालने से कुछ ही महीनों बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से करीब 58 करोड़ भारतीय औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, जिनमें लगभग आधी महिलाएं हैं। इनमें से बहुत से लोगों के लिए बैंक खाता और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का यह पहला अनुभव था। इसी मजबूत

आधार पर यूपीआई का विस्तार हुआ। अक्टूबर 2016 में जहां यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 1 लाख लेन-देन होते थे, वहीं 2026 में एक महीने में 24.5 अरब से अधिक लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य करीब 29 लाख करोड़ रुपये रहा। आज भारत यूपीआई को डिजिटल सार्वजनिक अवसरचरणा के ऐसे मॉडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिसे अन्य देश भी अपना सकते हैं। यह बदलाव केवल वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भौतिक अवसरचरणा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। रेलवे विद्युतीकरण 2014 से पहले के कुल नेटवर्क के लगभग पांचवें हिस्से से बढ़कर आज 99.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है। चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुने से भी अधिक हो गई है। 2014 से 2026 के बीच निर्मित ग्रामीण सड़कों की लंबाई, उससे पहले के 14 वर्षों में निर्मित ग्रामीण सड़कों से भी अधिक है। आज ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 22 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध है, जबकि पहले यह मुश्किल से 12 घंटे थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता कवरेज भी पांच वर्षों के भीतर 39 प्रतिशत से बढ़कर पूर्ण कवरेज तक पहुंच गई। इन आंकड़ों के पीछे आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आए बदलाव की कहानियां हैं, किसी ऐसे परिवार की, जिसे अब घर में बिजली मिलती है; ऐसे विद्यार्थी की, जो रात में रोशनी में पढ़ाई कर सकता है; या ऐसे परिवार की, जिसे बेहतर सड़कों और आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिलती है। अवसरचरणा का वास्तविक प्रभाव इन्हीं रोजमर्रा के अनुभवों में दिखाई देता है। इन प्रयासों

के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आयुष्मान भारत के तहत अब 62 करोड़ से अधिक वंचित और कमजोर नागरिकों को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। हाल ही में इसका विस्तार 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक तक भी किया गया है। 2014 के बाद से मैडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या दोगुने से अधिक हो चुकी है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किया है। जहां भारत लंबे समय तक रक्षा उपकरणों के साथ-साथ आत्मविश्वास के मामले में भी आयात पर निर्भर रहा, वहीं पिछले एक दशक में रक्षा निर्यात 56 गुना से अधिक बढ़कर 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया है। वहीं, चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बनाया, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की बदलती वैश्विक स्थिति ने भी विदेशों का ध्यान आकर्षित किया है। जब हाल ही में मोदी जी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने, तो दुनिया भर के नेताओं की ओर से उन्हें बधाइयां मिलीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लिखा कि यह उपलब्धि इस बात को दर्शाती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने बार-बार उनके नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने उन्हें मित्र, भाई और मार्गदर्शक के रूप में संबोधित किया। अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों जैसे अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं ने भी परिणामों को आकार देने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका का उल्लेख किया है। ये वक्तव्य विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच उनके नेतृत्व को मिली वैश्विक महत्ता को दर्शाते हैं। फिर भी, यदि मोदी जी से पूछा जाए कि ये पच्चीस वर्ष उनके लिए क्या मायने रखते हैं, तो शायद इसका उत्तर किसी आंकड़े या रैंकिंग में नहीं मिलेगा। इसके बजाय, इसका उत्तर एक प्राचीन संस्कृत आदर्श में मिल सकता है, सर्वं भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी सुखी हों, सभी रोग और दुख से मुक्त हों। 2001 में गुजरात से लेकर 2026 में भारत तक की उनकी यात्रा में शासन को सेवा के माध्यम के रूप में देखने का विचार लगातार प्रमुख रहा है। यह दृष्टि 'सेवा' की भावना में निहित है, इस विश्वास में कि सार्वजनिक पद दूसरों के कल्याण के प्रति जिम्मेदारी लेकर आता है।

नागरिक की पहचान एक, दस्तावेज अनेक और सुधार का रास्ता उलझा हुआ, कागजों का दुश्मन आखिर कब टूटेगा?

डिजिटल व्यवस्था के बावजूद त्यों बनी हुई है पहचान की उलझान- डिजिटल प्रणाली के जरिए इस जटिल स्थिति को कई स्तरों पर सरल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि डिजिटल होने भर से प्रक्रिया नागरिक-केंद्रित नहीं हो जाती। जन सेवा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टलों ने आवेदन तथा दस्तावेज जमा करने की सुविधा बढ़ाई है, पर अंतिम सत्यापन और निर्णय का अधिकार अलग-अलग विभागों के पास बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक को एक ही सूचना बार-बार अलग संस्थाओं के सामने सिद्ध करनी पड़ सकती है।

(विकेश कुमार बडोला)

सत्यापन की प्रक्रिया में नागरिक को हर बार शून्य से शुरूआत करने के लिए विवश करना प्रशासनिक सुविधा नहीं, नागरिक के समय और श्रम पर अनावश्यक बोझ है। तकनीक का लाभ तभी व्यापक होगा, जब विभागीय डेटाबेस के बीच सुरक्षित और स्पष्ट समन्वय के साथ त्रुटि-सुधार की जिम्मेदारी भी तय हो। आधुनिक दौर में नागरिक की पहचान केवल नाम और चेहरे तक सीमित नहीं रह गई है। जन्म प्रमाणपत्र से लेकर आधार, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। इनका उद्देश्य नागरिक और राज्य के बीच भरोसेमंद पहचान स्थापित करना है। मगर जब एक ही व्यक्ति की अलग-अलग संस्थाओं में दर्ज सूचनाओं में मामूली अंतर रह जाता है, तो यही व्यवस्था सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बनने लगती है। समस्या दस्तावेज की संख्या भर नहीं है। असली कठिनाई उनके बीच समन्वय, जिम्मेदारी और सुधार की प्रक्रिया को लेकर है। किसी प्रमाणपत्र में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पते या अन्य विवरण में त्रुटि हो जाए, तो नागरिक को अक्सर संबंधित कार्यालय, पोर्टल या सेवा केंद्र के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक दस्तावेज में सुधार के लिए दूसरे दस्तावेज की मांग की जाती है और दूसरे में सुधार के लिए पहले प्रमाणपत्र का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे में नागरिक एक ऐसे दुश्मन में फंस जाता है, जिसका हल उसके हाथ में नहीं होता।

डिजिटल व्यवस्था के बावजूद क्यों बनी हुई है पहचान की उलझन? – डिजिटल प्रणाली के जरिए इस जटिल स्थिति को कई स्तरों पर सरल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि डिजिटल होने भर से प्रक्रिया नागरिक-केंद्रित नहीं हो जाती। जन सेवा केंद्रों



और ऑनलाइन पोर्टलों ने आवेदन तथा दस्तावेज जमा करने की सुविधा बढ़ाई है, पर अंतिम सत्यापन और निर्णय का अधिकार अलग-अलग विभागों के पास बना हुआ है।इसका अर्थ यह है कि नागरिक को एक ही सूचना बार-बार अलग संस्थाओं के सामने सिद्ध करनी पड़ सकती है। तकनीक का लाभ तभी व्यापक होगा, जब विभागीय डेटाबेस के बीच सुरक्षित और स्पष्ट समन्वय के साथ त्रुटि-सुधार की जिम्मेदारी भी तय हो। आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसका उपयोग अनेक सेवाओं में पहचान के सत्यापन के लिए किया जाता है। बैंक खातों और मोबाइल सेवाओं से जुड़े विवरणों में आधार का इस्तेमाल व्यापक है। ऐसे में आधार या उससे जुड़े रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा अन्य सूचना की गड़बड़ी का असर दूसरी सेवाओं पर पड़ सकता है। प्रश्न यह है कि गलती हुई कहाँ है। यदि त्रुटि किसी विभागीय रिकॉर्ड में हुई है, तो उसके सुधार का पूरा बोझ

नागरिक पर डालना प्रशासन की न्यायसंगत भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। नागरिक से आवश्यक प्रमाण मांगना अलग बात है, लेकिन विभागों के पास उपलब्ध प्रमाणों और अभिलेखों का परस्पर सत्यापन करना व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहां एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है- राज्य को नागरिक से पहचान का प्रमाण मांगने के साथ अपनी संस्थागत पहचान और जिम्मेदारी भी स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने दशकों तक कर चुकाया है, मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उसके जन्म, शिक्षा, संपत्ति या पारिवारिक संबंधों के सरकारी अभिलेख उपलब्ध हैं, तो इन सूचनाओं को अलग-अलग द्वीपों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सत्यापन की प्रक्रिया में नागरिक को हर बार शून्य से शुरूआत करने के लिए विवश करना प्रशासनिक सुविधा नहीं, नागरिक के समय और श्रम पर अनावश्यक बोझ है। एकीकृत व्यवस्था हो, लेकिन नागरिक के

अधिकारों के साथ इसलिए एकीकृत नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणपत्र तंत्र की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसे किसी नई पहचान संख्या या अतिरिक्त कागजी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा प्रणालियों के बीच समन्वयकारी ढाँचे के रूप में विकसित किया जाना अधिक उपयोगी होगा। केंद्र और राज्यों के संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, आधार व्यवस्था, निर्वाचन तंत्र, पासपोर्ट प्रणाली तथा अन्य वैधानिक संस्थाओं के बीच स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। इसमें यह तय होना चाहिए कि कौन-सा मूल रिकॉर्ड किस संस्था के पास रहेगा, कौन-सी सूचना किस परिस्थिति में साझा की जा सकती है, गलती सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी और नागरिक को आवेदन का कौन-सा रास्ता मिलेगा। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष घर-द्वार तक सेवा पहुंचाने की अवधारणा हो सकता है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उन नागरिकों के लिए, जिन्हें बार-बार कार्यालय जाना कठिन होता है, उन्हें प्रशिक्षित सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन और दस्तावेजी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए निर्धारित शुल्क हो, तो वह पारदर्शी और सीमित हो तथा गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए छूट या निशुल्क सेवा का प्रावधान रखा जाए। नागरिकता के प्रश्न पर विशेष सावधानी जरूरी है। आधार संख्या नागरिकता का प्रमाण नहीं है और किसी पहचान दस्तावेज की मौजूदगी अपने आप भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं करती। इसलिए नागरिकता निर्धारित करने की किसी भी व्यवस्था को मौजूदा कानूनों, तय प्रक्रियाओं और न्यायिक संरक्षण के अनुरूप ही काम करना होगा। केवल संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन लेना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। नागरिकता से जुड़े मामलों में सुनवाई, प्रमाण प्रस्तुत करने, अपील और स्वतंत्र समीक्षा की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

सेवानिवृत्ति के बाद भी संगठन को मिलेगा दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ : कमल वर्मा

राजपत्रित अधिकारी संघ ने भूपेंद्र पांडेय एवं नंदलाल चौधरी का किया अभिनंदन

रायपुर (जनता के गोठ)। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के तत्वावधान में इंद्रावती भवन में संगठन के लिए लंबे समय तक समर्पित रहे श्री भूपेंद्र पांडेय, अपर संचालक एवं श्री नंदलाल चौधरी, संयुक्त संचालक के सेवानिवृत्त होने के उपरांत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के संगठनात्मक योगदान को स्मरण करते हुए उनका सम्मान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के उपाध्यक्ष श्री दिलदार मरावी ने कहा कि दोनों अधिकारी अपने शासकीय

दायित्वों के प्रति सदैव समर्पित रहे तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे।

श्री डी.पी. टावरी एवं श्री पूषण साहू ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी संघ को मजबूत एवं संगठित करने में दोनों अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया।

श्री अभिषेक शर्मा एवं श्री पी.एल. साह्रा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव एवं मार्गदर्शन का लाभ कर्मचारी संगठनों को मिलता रहना चाहिए। वहीं श्री संजय अम्बस्त एवं श्री मौसम मेहरा ने उनके संगठनात्मक योगदान को रेखांकित करते हुए अधिकारियों से अपने अधिकारों के लिए संगठित प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। श्री जय कुमार साहू एवं



श्री संतोष कुमार वर्मा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के विभिन्न आंदोलनों को सफल बनाने में दोनों अधिकारियों के योगदान एवं रणनीतिक

भूमिका का उल्लेख करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। **संगठन को गति देने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान : कमल वर्मा**

संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल वर्मा ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी संघ को प्रदेशभर में संगठित करने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने में

एकता से शासकीय सेवकों को मिला आर्थिक लाभ : नंदलाल चौधरी

अभिनंदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री नंदलाल चौधरी ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी संघ के संबंध में उन्होंने जो सपना देखा था, वह आज साकार हो चुका है। संगठन की एकजुटता और संघर्ष के माध्यम से प्रदेश के शासकीय सेवकों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों से भविष्य में भी एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन संघ के महासचिव श्री अविनाश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को संघ के साथ निरंतर जोड़कर उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलता रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में श्री डी.पी. टावरी ने सफल आयोजन के लिए सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री भूपेंद्र पांडेय एवं श्री नंदलाल चौधरी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों की सक्रिय भूमिका एवं अनुभव संगठन की महत्वपूर्ण पूंजी है। भविष्य में भी संगठनात्मक गतिविधियों एवं आंदोलनों के दौरान उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लिया जाएगा।

‘बच्चों के अंदर अपना बचपना ढूंढता हूं..’ : जमीन पर बैठकर बच्चों संग खेले श्री अरुण साव

रायपुर (जनता के गोठ)। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव सेवा संकल्प अभियान के तहत आज लोसमी में आंगन मिलन उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नन्हें बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेला और उनके साथ घुल-मिलकर खेह-दुलार से बातें की। बच्चों के साथ बिताए इन पलों में श्री साव का सहज और आत्मीय अंदाज नजर आया। उन्होंने बच्चों को मिठाई और खिलौने भी दिए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आंगन मिलन उत्सव में अन्नप्राशन और गोवर्भराई की रस्म भी संपन्न की गई।

कार्यक्रम में आंगनबाड़ी परियोजना अधिकारियों, सुपरवाइजर्स एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आंगन मिलन उत्सव में नन्हें बच्चों ने लाल टमाटर बड़े मजेदार, आंगनबाड़ी जाएंगे और आलू कचालू बेटे कहां गए थे जैसे बाल गीत सुनाए। बच्चों की मासूम प्रस्तुतियों और खिलखिलाहट से पूरा आंगनबाड़ी परिसर खुशनुमा हो



गया। इस दौरान आयोजित सुपोषण चौपाल में बच्चों और माताओं के पोषण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि स्वस्थ और सुपोषित बचपन ही मजबूत भविष्य की नींव है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा अभियान के

माध्यम से पोषण को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इस पहल की प्रशंसा की है। श्री साव ने कहा कि बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ परिवार और समाज की भागीदारी भी जरूरी है।

बस्तर की बदली तस्वीर को देश दुनिया तक पहुंचाएं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर – राज्यपाल श्री डेका



रायपुर (जनता के गोठ)। राज्यपाल श्री रमन डेका ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। कोशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बस्तर में विकास के साथ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भय का वातावरण धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बस्तर में हो रहे इन सकारात्मक बदलावों को देश-विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल आज दिल्ली से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के दल से मुलाकात के दौरान संबोधित कर रहे थे।

ये सभी इन्फ्लुएंसर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद आए बदलाव, विकास कार्यों, स्थानीय जनजीवन और पर्यटन की संभावनाओं को करीब से जाना और समझा।

इन्फ्लुएंसर ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने तीन दिन बस्तर में बिताए और इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों और गांवों का भ्रमण कर वहां की वर्तमान स्थिति को देखा। उन्होंने बताया कि

मीडिया के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होने और बस्तर में हो रहे बदलाव की जानकारी मिली थी। इसी बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने के उद्देश्य से वे यहां पहुंचे हैं। इन्फ्लुएंसर ने कहा कि बस्तर में उन्हें शांति और सुकून का अनुभव हुआ। यहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। सड़क संपर्क बेहतर हुआ है तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार के लिए किए जा रहे प्रयास भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में उन्होंने जितने बदलाव की कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। वे अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इन अनुभवों को देश-दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिससे बस्तर के प्रति बनी पुरानी धारणाएं दूर हों और अधिक लोग यहां पर्यटन के लिए आएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि बस्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे कम रोज स्कूल जाते हैं। प्रधानमंत्री विकास योजनाओं के माध्यम से गांवों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बस्तर के शहरों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो विकास की गति भी तेज होगी और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।

एनआईटी रायपुर द्वारा राजिम में ‘स्वच्छता अभियान 2026’ एवं स्वच्छता से समृद्धि विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

उन्नत भारत अभियान क्लब ने राजिम में स्वच्छता रैली और जन-जागरूकता गतिविधियों का किया संचालन

रायपुर (जनता के गोठ)। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर द्वारा स्वच्छता, नागरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2026 को बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन पहलों के अंतर्गत संस्थान के ‘उन्नत भारत अभियान’ (ऊँ) क्लब द्वारा ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी राजिम में ‘स्वच्छता अभियान 2026’ चलाया गया, वहीं संस्थान की साहित्यिक समिति ‘लिटराटी’ द्वारा ‘स्वच्छता से समृद्धि’ विषय पर केंद्रित निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

राजिम में आयोजित स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं और युवाओं के बीच स्वच्छता प्रथाओं एवं समुचित अपशिष्ट निपटान के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम एनआईटी रायपुर के ऊँ क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. सुधाकर पांडे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसमें पीआई समन्वयक डॉ. गोवर्धन भट्ट, ऊँ क्लब के फ़ैकल्टी इंचार्ज डॉ. दीपिका अग्रवाल व डॉ. शैलेंद्र कुमार निपाटी, ऊँ सहायक श्री विजय वर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज की।

अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने श्रमदान कर आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की गहन सफाई की तथा स्थानीय निवासियों व



दुकानदारों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने समुदाय को कचरे का पृथक्करण कर निर्धारित स्थलों पर निस्तारण करने, एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और खुले में कचरा न फेंकने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा एक प्रभावी स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन, स्वच्छ व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक जन-जागरूकता का प्रसार किया गया।

इसी क्रम में, युवाओं में वैचारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु एनआईटी रायपुर की लिटराटी समिति द्वारा डॉ. वाई. विजय बाबू एवं डॉ. चेतना एस. राजपूत के मार्गदर्शन में

‘स्वच्छता से समृद्धि’ विषयक निबंध लेखन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर स्वच्छता, नागरिक कर्तव्यों, पर्यावरणीय संवहनीयता और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में स्वच्छ परिवेश की अपरिहार्य भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। एनआईटी रायपुर की इन संयुक्त पहलों ने सामुदायिक भागीदारी, छात्र नेतृत्व और बौद्धिक अभिव्यक्ति को एक साझा मंच प्रदान किया। राजिम का स्वच्छता अभियान और संस्थान परिसर में आयोजित निबंध प्रतियोगिता न केवल स्वच्छ भारत मिशन की मूल भावना को सुदृढ़ करती है, बल्कि यह भी स्थापित करती है कि एक स्वस्थ एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास और सक्रिय नागरिक सहभागिता अनिवार्य हैं।

विहान’ से बदली दिनेश्वरी सोरी की तकदीर

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में स्वसहायता समूहों की भूमिका की मिसाल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम धनडोंगरी की श्रीमती दिनेश्वरी सोरी ने पेश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘विहान’ से जुड़ने के बाद उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के जरिए अपनी पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्रीमती दिनेश्वरी सोरी ‘जय सेवा जय बुढ़ा देव स्वसहायता समूह’ से जुड़ीं। शुरुआत में पूंजी की कमी उनके सामने चुनौती थी। समूह और ग्राम संगठन से मिले वित्तीय सहयोग से उन्होंने अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीदी और उत्पादन शुरू किया। इसके बाद बैंक से एक लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण लेकर कारोबार का विस्तार किया। स्थानीय बाजार की मांग के अनुकूप उन्होंने एक से अधिक आजीविका गतिविधियों को अपनाया। वर्तमान में वे मशरूम उत्पादन के साथ अगरबत्ती, साबुन, निरमा, गुलाल, मोगबत्ती, गोबर के दीये और चूड़ी निर्माण से जुड़े उत्पाद तैयार कर रही हैं।

स्वामी,मुदक,प्रकाशक,सहायक-शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग –मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एकट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com